

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 265/वि०स०/संसदीय/197(सं)/2016

दिनांक : 08 मार्च, 2017

अधिसूचना

प्रकीर्ण

श्री गया चरण दिनकर, नेता, बहुजन समाज पार्टी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के नियम-7 के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष, विधान सभा के विचारार्थ श्री अयोध्या प्रसाद पाल, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा के विरुद्ध दिनांक 17-12-2016 को दायर की गयी याचिका पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा दिनांक 08-03-2017 को किया गया विनिश्चय एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ अधिसूचित किया जाता है :-

अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश

श्री गया चरण दिनकर द्वारा श्री अयोध्या प्रसाद पाल के विरुद्ध उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई याचिका पर

निर्णय

1-श्री गया चरण दिनकर, नेता बहुजन समाज पार्टी, विधान मण्डल दल दिनांक 17-12-2016 को उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के नियम-7 सपठित संविधान की दसवीं अनुसूची एवं अनुच्छेद-191(2) के अन्तर्गत श्री अयोध्या प्रसाद पाल, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध याचिका प्रस्तुत की गयी है।

2-संक्षेप में याची का यह कथन है कि बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है तथा इसे निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। याची के अनुसार विपक्षी आम चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर दिनांक 06 मार्च, 2012 को विधान सभा क्षेत्र संख्या-241, अयाह शाह विधान सभा जिला-फतेहपुर से उत्तर प्रदेश की सोलहवीं विधान सभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे, जिसकी अधिसूचना चुनाव आयोग द्वारा 06-03-2012 को निर्गत की गयी थी। याची द्वारा यह भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा जारी दलीय सूची में विपक्षी का नाम बहुजन समाज पार्टी सदस्य के रूप में अंकित है।

3-याची के अनुसार भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रस्तर-(1) (ए) में यह उल्लिखित है कि यदि कोई सदस्य जिस पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुआ है उस पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है तो वह विधान सभा के सदस्य के रूप में निरर्ह हो जायेगा।

4-याची ने इस पर बल दिया है कि विपक्षी श्री अयोध्या प्रसाद पाल ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे, द्वारा स्वेच्छा से दिनांक 21-09-2016 को बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है।

5-याची द्वारा यह कहा गया है कि विपक्षी की सदस्यता छोड़ने की सूचना दिनांक 22-09-2016 को समाचार-पत्र अमर उजाला में छपी है।

6-याची के अनुसार दिनांक 21-09-2016 को बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता छोड़ने के उपरान्त उन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल हो गये हैं तथा वे लगातार समाजवादी पार्टी के सभाओं एवं कार्यक्रमों में शिरकत करते रहे हैं, इस आशय की खबर दिनांक 30-09-2016 के दैनिक समाचार-पत्र अमर उजाला में छपी है।

7-याची द्वारा यह भी कहा गया है कि विपक्षी द्वारा बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ने के उपरान्त वह भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अनुच्छेद-2(1)(क) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में निरह हो गये हैं।

8-अन्त में श्री गया चरण दिनकर याची द्वारा यह प्रार्थना की गयी है कि श्री अयोध्या प्रसाद पाल को भारत का संविधान की दसवीं अनुसूची सपठित अनुच्छेद-191(2) के अन्तर्गत विधान सभा की सदस्यता दिनांक 21-09-2016 से निरह घोषित करें एवं यह भी घोषित करें कि वह दिनांक 21-09-2016 से विधान सभा सदस्य के रूप में किसी भी सुविधा, भत्ता आदि हेतु अर्ह नहीं रहेंगे।

9-याचिका के समस्त प्रस्तुतों को उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरहता) नियमावली, 1987 के प्राविधानों के अन्तर्गत सत्यापित किया गया है तथा याचिका के साथ याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए एक शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। याची की ओर से संलग्नकों के रूप में विभिन्न समाचार-पत्रों की प्रतियां संलग्न की गयी हैं। याचिका के साथ संलग्न अभिलिखित साक्ष्य/उपाबन्धों को भी प्रमाणित किया गया है।

10-प्रस्तुत याचिका उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरहता) नियमावली, 1987 के अन्तर्गत प्राविधानों में वर्णित शर्तों को पूर्ण करती है। तदनुसार विपक्षी श्री अयोध्या प्रसाद पाल को उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरहता) नियमावली, 1987 के नियम-8(3) के अन्तर्गत याचिका की प्रति एवं उसके उपाबन्धों सहित प्रस्तुत करते हुए उन्हें अपना उत्तर/टिप्पणी प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।

11-विपक्षी द्वारा प्रस्तुत याचिका में अपना उत्तर प्रस्तुत करने हेतु यह अनुरोध किया गया कि राजनैतिक व्यस्तता के कारण मुझे कुछ समय प्रदान किया जाय।

12-विपक्षी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए एक माह का समय प्रदान किया गया है। न्यायहित में अतिरिक्त समय प्रदान किया गया।

13-याचिका पर सुनवाई हेतु 07-03-2017 की तिथि निर्धारित की गयी है। याची एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए। विपक्षी एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। याची के अधिवक्ता को सुनने के उपरान्त याचिका पर निर्णय सुरक्षित किया गया।

14-मैंने पत्रावली एवं सुसंगत अभिलेखों तथा साक्ष्यों का अवलोकन किया, जिसमें याची द्वारा प्रतिपक्षी श्री अयोध्या प्रसाद पाल के विरुद्ध मुख्य रूप से इस आधार पर निरहता का अनुरोध किया गया कि उन्होंने स्वेच्छा से बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता त्याग दी है।

15-भारत में संसदीय लोकतंत्र की प्रगति के दौरान यह अनुभव किया गया कि दल-बदल के कारण परिपक्व लोकतंत्र की प्रगति में बाधा आ रही है। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल

की विचारधारा के आधार पर उसके सदस्य के रूप में निर्वाचित होता है तो उससे यह अपेक्षित है कि वह उस दल की विचारधारा के अनुसार प्रतिबद्धता रखते हुए कार्य करेगा। मतदाता किसी प्रत्याशी को उसके दल के परिप्रेक्ष्य में मतदान करता है, अतः यदि निर्वाचित होने के पश्चात् कोई सदस्य दल-बदल करता है तो वह जनता के साथ धोखा है। दल-बदल की प्रथा अलोकतांत्रिक है क्योंकि यह निर्वाचन के परिणामों को नकारती है। इसके अतिरिक्त, दल-बदल के कारण कई बार सरकारों की अस्थिरता भी उजागर हुई जोकि जनहित के विपरीत है। इन्हीं सब उद्देश्यों एवं कारणों को दृष्टिगत रखते हुए संविधान में बावनवें (52वें) संशोधन का समावेश किया गया जिससे कि दल-बदल की प्रथा को रोका जा सके। संविधान की दसवीं अनुसूची में ऐसे विभिन्न आधार प्राविधानित किये गये जिनके उत्पन्न होने से सदन के निर्वाचित सदस्यों की निरर्हता घोषित की जा सके। प्रारम्भ में एक-तिहाई सदस्यों के समूह तक के दल-बदल को मान्यता प्रदान करते हुए संरक्षित किया गया, परन्तु समय के साथ यह अनुभव किया गया कि इससे भी वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो रही है, अतः अन्ततः दल-बदल को पूर्णतया असंवैधानिक घोषित किया गया। दल-बदल कानून के संविधान में तदनुसार समावेश के पश्चात् यदि दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई याचिकाओं का त्वरित निस्तारण नहीं किया जाता तो संविधान की योजनाओं में निहित प्राविधानों का हनन होगा एवं वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति भी नहीं होगी। तदनुसार दसवीं अनुसूची में प्रस्तुत की गई याचिकाओं के निस्तारण के विषय में अनावश्यक विलम्ब किया जाना असंवैधानिक है एवं दसवीं अनुसूची के उद्देश्यों के विपरीत है तथा संसदीय लोकतंत्र के लिए हानिकारक है।

16-के प्रकरण में निम्नलिखित मा10 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दसवीं अनुसूची के अभिप्राय तथा उद्देश्यों एवं उसमें निहित मन्तव्यों को “किहोटाहोलोहान एआईआर 1993 एससी 412)”रूप से परिभाषित किया गया है :-

“...these provisions in the Tenth Schedule give recognition to the role of political parties in the political process. A political party goes before the electorate with a particular programme and it sets up candidates at the election on the basis of such programme. A person who gets elected as a candidate set up by a political party is so elected on the basis of the programme of that political party. The provisions of paragraph 2(1)(a) proceed on the premise that political propriety and morality demand that if such a person, after the election, changes his affiliation and leaves the political party which had set him up as a candidate at the election, then he should give up his membership of the legislature and go back before the electorate.”

17-मा10 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डा10 महाचन्द्र प्रसाद सिंह प्रति चेरमैन बिहार लेजिस्लेटिव कौंसिल एवं अन्य (2004, 8 एससीसी 747) के मामले में सभापति अथवा अध्यक्ष की दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत भूमिका परिभाषित की गई है एवं यह अवधारित किया गया है कि दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत सभापति अथवा अध्यक्ष निरर्हता के प्रश्न पर विनिश्चय करते समय स्वविवेक धारित नहीं करते हैं वरन् उनकी भूमिका प्रकरण के वर्णित तथ्यों को एकत्र करने एवं उन्हें सुनिश्चित करने की होती है। प्रमाणिक रूप से प्रकरण के सम्बन्धित समस्त तथ्यों के विषय में समाधान हो जाने पर अध्यक्ष अथवा सभापति दसवीं अनुसूची के सुसंगत प्राविधानों को प्रकरण के तथ्यों के विषय में लागू करते हुए अपना निर्णय प्रदान करेंगे। मा10 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के सुसंगत अंश निम्नवत् है :-

“Paragraph 6 says that where any question arises as to whether a member of the House has become subject to disqualification under the Schedule, the same shall be referred for the decision of the Chairman or, as the case may be, the Speaker of the House

and his decision shall be final. Therefore, the final authority to take a decision on the question of disqualification of a member of the House vests with the Chairman or the Speaker of the House. It is to be noted that the Tenth Schedule does not confer any discretion on the Chairman or Speaker of the House. Their role is only in the domain of ascertaining the relevant facts. Once the facts gathered or placed show that a member of the House has done any such act which comes within the purview of sub-paragraph (1), (2) or (3) of Paragraph 2 of the Tenth Schedule, the disqualification will apply and the Chairman or the Speaker of the House will have to make a decision to that effect.”

18-मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई उक्त विधि व्यवस्थाओं के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत जो याचिकायें अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं, उनमें मुख्य रूप से अध्यक्ष का कार्य तथ्यों को सुनिश्चित करके निर्णय प्रदान करने का है तथा इसमें अध्यक्ष अपने स्वविवेक से कोई कार्य नहीं कर सकते। प्रस्तुत प्रकरण में याची द्वारा यह कहा गया है कि विपक्षी श्री अयोध्या प्रसाद पाल द्वारा दिनांक 21-09-2016 को अपने मूल राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता त्याग कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली गयी जोकि यह दर्शित करते हैं कि उन्होंने अपने मूल राजनीतिक दल की सदस्यता का त्याग कर दिया है।

19-मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दसवीं अनुसूची के प्रस्तर 2 (1) (क) की परिधि एवं उसके विस्तार के संदर्भ में 'किहोटोहोलोहान, रवि एस० नायक एवं जी० विश्वनाथन (1996) 2 एस०सी०सी०' के मामलों में पारित निर्णयों के अन्तर्गत व्याख्या प्रदर्शित की है तथा यह अवधारित किया है कि सदन के किसी सदस्य द्वारा राजनीतिक दल की सदस्यता को स्वेच्छापूर्वक त्यागने का कृत्य प्रत्यक्ष (Express) अथवा विवक्षित (Implied) हो सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई विधिक व्यवस्थाओं के अनुसार सदन का कोई सदस्य विवक्षित रूप से अपने आचरण द्वारा भी राजनीतिक दल की सदस्यता का स्वेच्छा से त्याग कर सकता है।

20-याचिका में अभिलिखित तथ्यों के सम्बन्ध में विपक्षी श्री अयोध्या प्रसाद पाल द्वारा सुनवाई के समय उपस्थित न होने अथवा अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत न करने से यह स्पष्ट है कि दिनांक 21-09-2016 को उनके द्वारा समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रवि एस० नायक प्रति यूनियन ऑफ इंडिया (ए०आई०आर० 1994, एस०सी० 1558) में पारित निर्णय के अन्तर्गत समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों को साक्ष्य के रूप में दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई याचिकाओं के निस्तारण हेतु संज्ञान में लिये जाने के विषय में मान्यता प्रदान की है जोकि निम्नवत् है :-

“As regards the reference to the news papers in the impugned order passed by the Speaker it appears that the Speaker, in his order, has only referred to the photographs as printed in the newspapers showing the appellants with Congress (I) MLAs and Dr. Barbosa, etc. when they had met the Governor with Dr. Wilfred D’Souza who had taken them to show that he had the support of 20 MLAs. The High Court has rightly pointed out that the Speaker, in referring to the photographs was drawing an inference about a fact which had not been denied by the appellants themselves, viz., that they had met the Governor along with Dr. Wilfred D’Souza and Dr. Barbosa on December 10, 1990 in the company of congress (1) MLAs, etc. The talk between the Speaker and the Governor also refers to the same fact. In view of the absence of a denial by the appellants of the averment that they had met the Governor on December 10, 1990 accompanied by Dr. Barbosa and Dr. Wilfred D’Souza and Congress MLAs the controversy was confined

to the question whether from the said conduct of the appellants an inference could be drawn that they had voluntarily given up the membership of the MGP. The reference to the newspaper reports and to the talk which Speaker had with the Governor, in the impugned order of disqualification does not, in these circumstances, introduce an infirmity which would vitiate the said order as being passed in violation of the principles of natural justice.”

21—माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त की गई उपर्युक्त अवधारणाओं से यह स्पष्ट है कि समाचार-पत्रों को दसवीं अनुसूची के अन्तर्गत याचिकाओं के निस्तारण हेतु संज्ञान में लिया जाना सर्वथा औचित्यपूर्ण है। प्रतिपक्षी की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य अथवा आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे कि उपर्युक्त समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों का कोई खण्डन किया गया हो, अतः याची द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्य एवं तर्क विधिक रूप से मान्य है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के विश्लेषण एवं विवेचना से यह स्पष्ट है कि श्री अयोध्या प्रसाद पाल द्वारा दिनांक 21-09-2016 को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किये जाने के फलस्वरूप उन्होंने स्वेच्छा से अपने मूल राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता को तत्समय स्वेच्छा से त्याग दिया था। अतः श्री अयोध्या प्रसाद पाल को दिनांक 21-09-2016 से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता से निरह माना जायेगा।

22—माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्री राजेन्द्र सिंह राणा प्रति श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, (ए0आई0आर0/एस0सी0 1305, 2007) में यह स्पष्ट रूप से अवधारित किया गया है कि निरहता उसी दिन से लागू एवं प्रभावी मानी जायेगी जिस दिन से सम्बन्धित सदस्य द्वारा स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल का त्याग किया गया हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय के निम्नलिखित अंश सुसंगत हैं :-

“As we see it, the act of disqualification occurs on a member voluntarily giving up his membership of a political party or at the point of defiance of the whip issued to him. Therefore, the act that constitutes disqualification in terms of paragraph 2 of the Tenth Schedule is the act of giving up or defiance of the whip. The fact that a decision in that regard may be taken in the case of voluntarily giving up by the Speaker at a subsequent point of time cannot and does not postpone the incurring of disqualification by the act of the legislator. Similarly, The fact that the party could condone the defiance of a whip within 15 days or that the Speaker takes the decision only thereafter in those cases, cannot also pitch the time of disqualification as anything other than the point at which the whip is defied. Therefore in the background of the object sought to be achieved by the Fifty-Second Amendment of the Constitution and on a true understanding of paragraph 2 of the Tenth Schedule, with reference to the other paragraphs of the Tenth Schedule, the position that emerges is that the Speaker has to decide the question of disqualification with reference to the date on which the member voluntarily gives up his membership or defies the whip. It is really a decision ex post facto. The fact that in terms of paragraph 6 a decision on the question has to be taken by the Speaker or the Chairman, cannot lead to a conclusion that the question has to be determined only with reference to the date of the decision of the Speaker. An interpretation of that nature would leave the disqualification to an indeterminate point of time and to the whims of the decision making authority. The same would defeat the very object of inacting the law. Such an interpretation should be avoided to the extent possible. We are, therefore, of the view that

the contention that only on a decision of the Speaker that the disqualification is incurred, cannot be accepted.”

23—उपर्युक्त वर्णित तथ्यों, विधिक प्राविधानों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई विधि व्यवस्थाओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि श्री अयोध्या प्रसाद पाल ने दिनांक 21-09-2016 को अपने मूल राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता का स्वेच्छा से त्याग करते हुए दिनांक 21-09-2016 को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अतः श्री अयोध्या प्रसाद पाल के उक्त आचरण एवं कृत्य से यह स्पष्ट है कि उन्होंने तत्समय परोक्ष रूप से बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता को स्वेच्छा से त्याग दिया। वर्णित स्थिति में मेरा यह सुविचारित समाधान है कि श्री अयोध्या प्रसाद पाल के सन्दर्भ में भारत का संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रस्तर-2(1)(क) के प्रावधान आकर्षित होते हैं, जिसके फलस्वरूप श्री अयोध्या प्रसाद पाल दिनांक 21-09-2016 को निरर्हता से ग्रस्त हो गये।

आदेश

श्री गया चरण दिनकर द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका को स्वीकार किया जाता है। श्री अयोध्या प्रसाद पाल, सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र-241, अयाह शाह, जिला-फतेहपुर को भारत का संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रस्तर-2(1)(क) के अन्तर्गत दिनांक 21-09-2016 से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता से निरर्ह घोषित किया जाता है।

दिनांक : 08 मार्च, 2017

माता प्रसाद पाण्डेय,

अध्यक्ष,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश

आज्ञा से,

प्रमोद कुमार जोशी,

विशेष सचिव,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

संख्या : 265(1-18)/वि0स0/संसदीय/197(सं)/2016, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित:—

1. महामहिम राज्यपाल के प्रमुख सचिव को महामहिम राज्यपाल की सूचनार्थ,
2. मा0 मुख्य मंत्री के प्रमुख सचिव को मा0 मुख्य मंत्री की सूचनार्थ,
3. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
4. समस्त मा0 सदस्यगण, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
5. सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली,
6. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
7. प्रमुख सचिव, विधान सभा,
8. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य अनुभाग-1,
9. प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,

10. सचिव, विधि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली,
11. सरकारी सचिवालय के समस्त विभाग,
12. श्री गयाचरण दिनकर, नेता बहुजन समाज पार्टी, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
13. श्री अयोध्या प्रसाद पाल, जयराम नगर चौराहा, जनपद-फतेहपुर,
14. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क अनुभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
15. महासचिव, राज्य सभा, नई दिल्ली,
16. महासचिव, लोक सभा, संसद भवन, नई दिल्ली,
17. जिलाधिकारी, फतेहपुर,
18. विधान सभा सचिवालय के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग।

अशोक कुमार चौबे,
संयुक्त सचिव।